During review of sanctioned cases, it has been noticed that during the earlier stages, pension had been sanctioned on the basis of conviction and incomplete jail evidence. Before allowing such pensioners to continue to draw the pension they are being asked to furnish complete evidence. If in the absence of jail record, the persons produce other acceptable evidence such as co-prisoner certificates, their cases will be reconsidered and finalised after verification through the State Governments.

Agreement between BHEL and SIEMENS

2288. DR. SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Ministry has recommended to the Government a broad-based agreement between BHEL and SIEMENS;

(b) the cost of manufacture of turbines of rating 210 MW and below presently, and the estimated cost if the proposed agreement is implemented;

(c) the present capital-labour ratio of manufacture of the said turbines, and the likely level under the agreement; and

(d) when the Ministry has ascertained the opinion of the Ministry of Energy and the various State Electricity Boards on the proposed agreement, and if so, their reactions to the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) The proposal for a collaboration agreement between the BHEL and Siemens is under examination of the Foreign Investment Board which includes the representatives of this Ministry. Their recommendation is awaited.

(b) Disclosure of the cost of manufacture of turbines in this Government of India Undertaking would not be in the public interest. However, the cost of manufacture of turbines under the proposed agreement is expected to be comparable with those manufactured at present under equivalent levels of indigenisation.

(c) In this type of industry, it is difficult to work out such a ratio in the case of each product because the manufacturing facilities often overlap from one product to the other. However, in the turbines manufactured to the new design the material content and work content are anticipated to be less.

(d) The broad-based agreement covers products and a range of system engineering know-how of interest to a number of Ministries and utilities and industrial users. In such cases it is not possible to consult all the likely customers. In the case of the Ministry of Energy, however, their representative, as a Member of the Board of Directors of BHEL, was associated with the evaluation and the approval of the proposal at the Board level.

आदिवासियों पर अत्याचार

2289. श्री गोबिन्द मुण्डा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों पर अकारण अत्याचारों की खबर प्रतिदिन समाचार पत्रों में छप रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 में ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली ;

(ग) क्या सरकार ने इन अत्याचारों की बढ़ती हुई घटनाओं की जांच के लिए कोई समिति नियुक्त की है और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है और इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) , अनुसूचित जन जातियों पर अत्याचारों की रिपोर्ट समाचार पत्रों में आती रही है। राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई

सूचना के अनुसार वर्ष 1978-79 के दौरान, नवम्बर 1978 के अन्त तक अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की 1235 वारदातें हुई हैं।

(ग) तथा (घ). अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध किये जाने के लिए सामाजिक आर्थिक तथा अन्य परिस्थितियों का पता लगाना है। भारत सरकार ऐसी घटना के लिए उत्तरदायी मुख्य तत्वों को दूर करने के लिए उपायों को शीघ्र करने और तुरन्त प्रभावी कारंवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को विभिन्न सुझाव भी दे रही है।

रूई के मूल्य में कमी

2290. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में इस वर्ष कपास की बहुत अच्छी फसल हुई है और क्या गत वर्ष उत्पादित रूई की अभी तक बिक्री नहीं की गई है जिस के परिणामस्वरूप रूई के मूल्य में भारी गिरावट आई है और इसके कारण किसानों की दशा बहुत खराब है, क्या गुजरात सरकार और किसान संघ ने इस के निर्यात किये जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है ;

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और रूई की कितनी गांठों का निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी ;

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जायेगी कि रूई निगम ही रूई की पूरी मात्रा की खरीद करें; और

(घ) क्या प्रत्येक जिले में खरीद केन्द्र, खोले जायेंगे जहां लंबे और छोटे रेशे वाली रूई का उत्पादन किया जा सके जिससे किसान अपने उत्पाद को अपने जिलों में बिक्री कर सकें ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख). कपास सलाहकार बोर्ड ने 16 जनवरी, 1979 को हुई अपनी बैठक में अनुमान लगाया था कि गुजरात में इस वर्ष (1978-79) कपास का उत्पादन लगभग 19.50 लाख गांठें होगा। पिछले मौसम में विना बिके स्टेपल कपास के निर्यात की अनुमति देने सम्बन्धी गुजरात सरकार के अनुरोध पर सरकार ने स्टेपल कपास की एक लाख गांठें निर्यात करने की अनुमति दे दी थी। हाल ही में, सरकार ने कपास की 1.5 लाख गांठों के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय किया है, जिसका राज्य-वार आवंटन अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). भारतीय कपास निगम, गुजरात में कपास तथा अच्छी तरह से दबाई गई गांठें खरीदता रहा है। चालू वर्ष में, निगम 27 केन्द्रों में कार्य कर रहा है। गुजरात सरकार से विचार विमर्श करने के पश्चात् चालू वर्ष में लगभग 4 लाख गांठे खरीदने का सुनिश्चय किया गया है। यदि और केन्द्र खोलने का कोई औचित्य होगा तो निगम इस पर विचार करेगा।

Setting up of Cement Plants for Irrigation Projects

2291. SHRI K. KUNHAMBU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Centre has advised the States to set up certain cement plants for speeding up the construction of irrigation projects; and

(b) if so, the names of States which applied for licences and action taken on them so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) At the Fourth Conference of State Ministers of Irrigation held at Trivandrum in February 1979 a proposal was mooted that the State Governments may consider setting up of captive cement factories for large irrigation projects.

(b) The Government of Gujarat have suggested that the proposed grinding unit of M/s. Narmada Cement Co. to be located at Magdalla should be treated as a captive plant for the construction of Navagam Dam. When this grinding unit is set up allocation of maximum quantities produced by it for the construction of Navagam Dam would be considered.

सीमेंट की कमी

2292. श्री कमलेश्वर प्रसाद यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, और जनवरी के महीनों में दिल्ली में सीमेंट की अप्रत्याशित कमी थी और यह कमी अभी तक बनी हुई है; और